



2026:AHC-LKO:19891

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट सी संख्या- 2044 वर्ष 2026

जब्बार अली शेख

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव (राजस्व), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ और 7 अन्य के माध्यम से।
.....विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता : दिलीप कुमार पाठक

विपक्षीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाठक, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राम कुमार मौर्य और अधिवक्ता श्री अवध कुमार पांडे की बातें सुनी, जिन्होंने विपक्षी संख्या 6, 7 और 8 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विपक्षीगण संख्या 6, 7 और 8 द्वारा गाटा संख्या 65, 0.1170 हेक्टेयर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने की मांग की है। यह भूमि नारायणपुर, परगना, तहसील बलरामपुर, जिला बलरामपुर में स्थित है और राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। याचिकाकर्ता ने अपने पूर्वजों की कब्रों की रक्षा करने और उक्त भूमि पर स्थित कब्रिस्तान के स्वरूप को संरक्षित करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपति उठाई है कि रिट याचिका में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने बलरामपुर जिले के नारायणपुर गांव में स्थित 0.1170 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली 0.1170 हेक्टेयर भूमि के संबंध में विपक्षी पक्ष संख्या 6, 7 और 8 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश हेतु व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) बलरामपुर के न्यायालय में नियमित वाद संख्या 28/2026 दायर किया है।

4. इस आपति को उठाए जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें मुकदमे की लंबितता के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि मुकदमा उस आधार से भिन्न आधार पर दायर किया गया है जिस आधार पर वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

5. किसी निजी व्यक्ति के बीच विवाद के संबंध में, उसी अनुतोष की मांग करते हुए दायर किए गए मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, और वह भी मुकदमे की वैधता और लंबित होने की जानकारी छिपाकर, रिट याचिका दायर करना याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के विवेकाधीन रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी अनुतोष का दावा करने से वंचित कर देता है। यह सर्वविदित कानून है कि इस न्यायालय के याचिका क्षेत्राधिकार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को निष्पक्ष भाव से न्यायालय में आना चाहिए और सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करते हुए याचिका दायर करनी चाहिए। उसी अनुतोष की मांग करते हुए मुकदमे का लंबित होना निश्चित रूप से एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्य है, और मुकदमे के लंबित होने की जानकारी छिपाने से रिट याचिका खारिज होने योग्य हो जाती है।

6. इसके अतिरिक्त, निजी व्यक्तियों के बीच संपत्ति विवाद के संबंध में नियमित मुकदमा ही उचित उपाय है और याचिकाकर्ता ने नियमित मुकदमा दायर करने का उपाय सही ढंग से अपनाया है। यह स्थापित कानून है कि जब कोई उपयुक्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा और याचिकाकर्ता पहले से ही वैकल्पिक उपाय का लाभ उठा रहा है, इसलिए रिट याचिका को खारिज करने का और भी अधिक कारण है।

7. याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमे की फाइलिंग और लंबितता के तथ्य को छिपाने को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ता के उपरोक्त दुराचार के लिए उस पर जुर्माना लगाना उचित है।

8. तदनुसार, रिट याचिका को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने लागत की राशि कम करने का अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि यदि लागत घटाकर 25,000 रुपये कर दी जाती है, तो याचिकाकर्ता आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर स्वयं ही यह राशि जमा कर देगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया अनुरोध स्वीकार किया जाता है और यह प्रावधान किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार के पास 25,000/- रुपये का खर्च जमा करे, अन्यथा वरिष्ठ रजिस्ट्रार संबंधित कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र भेजकर 50,000/- रुपये की वसूली की कार्यवाही शुरू करेंगे, जो इस राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेंगे और वसूली प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर इसे इस न्यायालय को भेज देंगे। इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि लखनऊ स्थित बाल गृह (लड़कियों के लिए) को भेजें, जो उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन संचालित और अनुरक्षित है।

मार्च 18, 2026

-अमित के-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।